(ख) क्या यह पुनर्वास कृषि, उद्योग अथवा अन्य किसी क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पुनर्वासित किए गए ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से संबंधित समूचे देश में आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास मुख्यत: रोजगार के क्षेत्र में किया गया है । मध्य प्रदेश में वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान क्रमश: 580, 540 और 421 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास उपलब्ध कराया गया। (इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उपलब्ध किए गए पुनर्वास के आंकड़े भी शामिल हैं।) उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा, भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार के लिए दो महत्वपूर्ण पुनर्वास योजनायें चलाई गई हैं :—

(1) भूतपूर्व सैनिको के लिए स्व-रोजगार–1 (सेमफैक्स–1) जिसमें भूत-पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितो को छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है और (2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार–2 (सेमफैक्स–2) जिसके अंतर्गत खेती और खेती से बाहर के क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है । मध्य प्रदेश में, सेमफैक्स-1 योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ किए जाने की तारीख (अर्थात् अप्रैल, 1987 से दिसम्बर, 1990) तक 120 भूतपूर्व सैनिकों को ऋण दिया गया । सेमफैक्स–2 योजना के अंतर्गत योजना प्रारम्भ किए जाने की तारीख अर्थात जनवरी, 1988 से मार्च, 1991 तक 22 भूतपूर्व सैनिकों को ऋण प्रदान किया गया ।

(घ) इस संबंध में पूरे देश से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

	1988	1989	1990
पुनर्वास	21,872	18,853	15,909
सेमफैक्स–1 अप्रैल, 1987 से दिसम्बर 1990 तक			4001
सेमफैक्स–2 जनवरी, 1988 से मार्च 1991 तक			1214

राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की अन्य पुनर्वास योजनायें चलाई जा रही हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं । इन योजनाओं में ये शामिल हैं :

औद्योगिक भू-खंडों के आवंटन में आरक्षण, परिवहन मार्ग के परमिट, आवास-स्थल, कृषि भूमि, दुग्ध केन्द्र, सब्जियों की दुकानें, जय जवान स्टालें आदि । इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निगरानी रखी जाती है ।

मारुति कारों का निर्यात

349. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के निर्यात में हाल ही में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में मारुति कारों के निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उनके निर्यात के संबंध हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री थी. के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1989–90 के 5223 वाहनों की तुलना में, वर्ष 1990–91 में मारुति उद्योग लिमिटेड केवल 4908 वाहनों का निर्यात कर सका । वर्ष 1991–92 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड ने 30–6–91 तक 3631 वाहनों का निर्यात किया है ।

(ग) सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड को निर्यात बढ़ाने के अपने प्रयासों में पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है और समय-समय पर, उसे आवश्यकतानुसार सहायता देती है ।

Revival of Deep Sea Fishing Industry

350. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what are the measures being implemented for revival of the deep sea fishing industry;

(b) what are the steps being taken to supply diesel oil to deep-sea fishing industry at international prices;

(c) at what stage of implementation is this particular recommendations; and

(d) what are reasons for delay in the implementation in this regard?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The following measures have been taken for revival of the Deep sea fishing industry:—

1. Government have decided to accord single window clearance of all proposals on Deep sea fishing.

2. Test fishing have been permitted to facilitate pre-investment study.

3. Vessels on long lease have been permitted to operate in the Indian EEZ.

4. In order to rehabilitate the existing deep sea fishing industry, a scheme for re-schedulement of loans provided to Deep sea fishing Cos. have been announced by SCICI.

(b) With effect from 1-4-1991, the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) have started operating a scheme to reimburse a part of the cost of the diesel oil consumed from 1-1-91 by deep sea fishing vessels.

(c) The scheme has already been implemented and pass books to parties, meeting the requirements, have already been despatched.

(d) There is no delay in implementing this scheme.

Price Fixed for Various Medicines under Drugs Price Control Order

351. SHRI G. G. SWELL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when and what was the price fixed for Magadol Tablets, Proxivon Capsules, Butaproxyvon Capsules, Spasmo Proxyvon Capsules, Ibudex Capsules, Analflam Tablets, Flagyl I. V. Injection, Brustan Tablets and Dextropic Cream under Drugs Price Control Order;

(b) what are the names of producers of these medicines;

(c) whether it is a fact that prices of these medicines have been overcharged; and

(d) if so, what was the price charged for and what action has been taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) The requisite information, to the extent available,